समाजवादी पार्टी
सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन :
एक नयी दिशा, एक नयी उम्मीद!
ग़रीबी के ख़िलाफ़
लड़ाई एक धोखा है
जब तक जाति और
लिंग के आधार पर
भेदभाव के ख़िलाफ़
लड़ाई ना हो
—डॉ राममनोहर लोहिया

बस, अब और नहीं!

समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाज के शोषित और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। हम समाज के सबसे ग़रीब, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज़ रहे हैं, इस पर हमें गर्व है।

विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने हमें जातिवादी कहकर हमारी उपेक्षा की है। अभिजात वर्ग के लोग हम पर सत्ता लोभी होने का आरोप लगाते हैं लेकिन यह पूरी तरह से झूठ है और इसे योजनाबद्ध तरीके से प्रचारित किया गया है ताकि कुछ खास शोषक वर्ग को लाभ मिलता रहे।

आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत शायद विश्व का सबसे बड़ा गैरबराबरी वाला देश है। अमीर और भी अमीर बनता जा रहा है। देश के 10 फीसदी समृद्ध (उच्च जाति के लोग) 60 फीसदी राष्ट्रीय सम्पत्ति पर काबिज हैं।

गरीब तबके की आय वृद्धि का स्तर मुद्रास्फीति के स्तर से कम है। भारत के आधे से ज़्यादा लोगों के पास देश का महज 8 फीसदी धन है। यानि कि गरीब दिन-प्रतिदिन और गरीब होता जा रहा है।

नोटबंदी सरकार की क्रूर चाल थी जिसने देश के गरीबों को सबसे ज़्यादा परेशान किया। नोटबंदी की वजह से किसान, कृषि श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, हुनरमंद और लाखों बेरोजगार युवा आज भी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हम लोग #महापरिवर्तन के लिए संकल्पित हैं

सामाजिक न्याय का अर्थशास्त्र

भारत में अत्यधिक असमानता को दूर करने के लिए तीन मोर्चों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तीन बिन्दु हैं सामाजिक गतिशीलता, आवास एवं आय। हम मानते हैं कि इन तीनों मोर्चों पर एक साथ ध्यान देने से देश में समानता और अत्यधिक प्रगतिशीलता आएगी।

हम लोगों ने समाजवादी पेंशन और लोहिया ग्रामीण आवास योजना को सफलता पूर्वक चलाया था। इस योजना के चलते गरीबों को काफी फायदा पहुंचा था।

हम वादा करते हैं कि इस योजना के तहत गरीब से गरीब परिवारों की मदद करेंगे।

समाजवादी पेंशन योजना के तहत हम जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को 3000 रुपए मासिक पेंशन देंगे। योजना के फंडों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत केंद्र की आवास योजना से तीन गुना ज्यादा गरीब परिवारों को आवास दिए । इन आवासों में दो कमरे, एक

शौचालय, सोलर पैनल, पंखा, लाइट और पानी की आपूर्ति की सुविधा दी है। ताकि गरीब परिवार के लोग भी गर्व के साथ अपना जीवन यापन कर सकें।

हमें कोई कारण नज़र नहीं आता है कि अमीर को और अधिक अमीर क्यों होना चाहिए। हमें यह भी कहीं से तर्कसंगत नहीं लगता है कि करोड़ों रुपए कमाने वाले और वेतनभोगी एक समान टैक्स का भुगतान करें।

हम 2.5 करोड़ से अधिक सम्पत्ति रखने वाले (भारतीय परिवारों का लगभग 0.1 फीसदी) परिवारों की कुल सम्पत्ति पर 2 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगाकर सामाजिक हस्तांतरण की वृद्धि का प्रस्ताव रखते हैं। हम ये भी मानते हैं कि ज्यादा अमीर लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का ब्रैकेट बनना चाहिए। जो अपनी सम्पत्ति को कई तरह से छुपाते हैं। जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 1 फीसदी होगा।

इससे करोड़ों परिवार गरीबी से मुक्त होंगे एवं यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम होगा। इस कदम से सतत विकास की दिशा में निरंतरता आएगी।

बहुमत का विकास

हमारा देश युवा है। देश की 50 फीसदी आबादी 25 साल से कम और 60 फीसदी आबादी 30 साल से कम की है। इसमें से ज्यादातर नौजवान बेरोजगार या अर्द्धबेरोजगार हैं। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बढ़ती बेरोजगारी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी मुद्दे पर बात करना देश के भविष्य को तबाह करने जैसा होगा।

हमारा युवा अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से नोटबंदी ने उनका रोजगार छीन लिया और जीएसटी ने छोटे उद्योगों को बंद कर दिया।

इसके बावजूद प्रधानमंत्री अपने कामकाज पर लोगों को भरोसा करने के लिए कह रहे हैं। जबकि हमारे नौजवानों को हर समस्या की बारीक समझ है।

नौजवान चाय और पकौड़े के स्टॉल लगाने की उनकी सलाह की निरर्थकता को बखूबी समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्हें जो बुनियादी तालीम दी गई है वो पर्याप्त नहीं है। गांव में पढ़े-लिखे नौजवान ये भी जानते हैं कि उनकी स्थिति शहरी क्षेत्रों में शिक्षित लोगों की तुलना में काफी खराब है। उन्हें ये भी पता है कि अच्छे शिक्षकों को ढूंढ़ना काफी मुश्किल है इसीलिए वो इन समस्याओं का सार्थक निदान चाहते हैं।

सार्वजनिक यातायात की लचर सुविधा ने स्थिति को और खराब कर दिया है। दूर स्थित अच्छे स्कूलों तक पहुंचने में लगने वाला वक्त काफी कष्टदायी है। अभिभावकों के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि उन्हें कॉलेजों के पास रहने की व्यवस्था कर सकें।

युवा, प्राईवेट कोचिंग पर समय और धन खर्च करने के बाद भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं।

इसलिए हम उत्तरप्रदेश में अपने सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों की ही भांति पूरे देश में बदलाव करना चाहते हैं।

हमें नये कान्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए मिशन मोड में नौकरियों और विकास कार्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं वर्तमान केंद्र सरकार की भांति गलतियां नहीं करना चाहते हैं। जिससे नए परिणाम दिए जा सकें।

शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार की जरूरत

सभी के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। स्कूलों का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है। गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा देने में देश असफल रहा है। इस कारण से देश की एक पीढ़ी रोजगार के अवसर से वंचित है। इस दिशा में महापरिवर्तन सिर्फ तभी आ सकता है जबकि जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाय। हम इस दिशा में अलग तरह से सोचते हैं ताकि देश के प्रत्येक छात्र को अनिवार्य, निःशुल्क एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों न हो।

परिवर्तन की गति में तेजी लाने की दिशा में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाय जिसमें शिक्षा में निरंतरता को बल मिले।

हम अभिभावकों की समस्याओं को दूर करने की दिशा में गम्भीरता से सोचते हैं ताकि उन्हें स्कूली शिक्षा के बजाय कोचिंग सेंटर्स पर बेतहाशा पैसा खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विषय विशेषज्ञों और गैर लाभकारी शैक्षिक संस्थाओं के साथ साझेदारी करेंगे ताकि सभी छात्रों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जा सके। विद्यालयों में इंटरैक्टिव पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं के जरिए परीक्षा प्रश्नावली और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। जिससे देश का प्रत्येक छात्र सुयोग्य शिक्षकों से उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा हासिल कर सकेगा।

हमारा मानना है कि यही वो तरीके हैं जिनके जरिए शिक्षा व्यवस्था में आई गिरावट को दूर किया जा सकेगा।

इसके अलावा जरूरतमंदों को लैपटॉप और टैबलेट्स भी दिया जाएगा ताकि वो अपनी शिक्षा को और बेहतर कर सकें।

देश के प्रत्येक छात्र को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी।

रोजगार के अवसर

हमारी सरकार बनने पर हम केंद्रीय आरक्षण के नवीन आंकड़ों को जारी करेंगे ताकि देश में प्रत्येक जाति की जनसंख्या का सही आंकलन किया जा सके।

इस पर अलग-अलग राय है कि आखिरकार देश में कितनी सरकारी नौकरियां हैं। नौकरियों की घोषणा किया जाना पर्याप्त नहीं हैं। चुनाव से चंद दिनों पहले 5,00,000 नौकरियों की घोषणा की गई हैं जिन्हें पूरा होने में पांच साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। हम लोग इस जटिल प्रक्रिया को न अपनाते हुए प्रत्येक साल 1,00,000 नौकरियां देंगे ताकि किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़ा। भर्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी कामकाज में आने वाली दिक्कतों के पीछे पर्याप्त मानव संसाधन का न होना है। देश में न तो पर्याप्त पुलिस बल है, न ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, न डॉक्टर्स हैं और ना ही नर्स हैं यह सूची और भी लम्बी है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या में जनसंख्या के आधार पर बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है।

हम लोग अग्रणी अर्थशास्त्रियों, सामाजिक विचारकों से मिलकर अध्ययन करेंगे कि देश में किस क्षेत्र में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है- उदाहरण के तौर पर 1.3 अरब जनसंख्या के लिए कितने पुलिस बल की आवश्यकता है?

हम लोग आवश्यक सरकारी विभागों में पांच साल के भीतर मानव संसाधन को चरणबद्ध तरीके से दोगुना करंगे।

औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार क्लस्टर्स

हमें ऐसी आर्थिक नीतियां नहीं चाहिए जो छोटे उद्यमों को मध्यम और मध्यम को बड़े बनने से रोकें। अगर हम वास्तव में देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं परन्तु देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित नहीं कर पा रहे हैं तब हमें दुबारा से सोचने की जरूरत है।

हम इंडस्ट्री इनोवेशन क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव रखते हैं जिन्हें शैक्षिक संस्थानों के करीब स्थापित किया जाएगा ताकि बाजार तक पहुंच बनी रहे। राज्य ऐसे सभी इनफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें विनियामक, तकनीकि और भौतिक संसाधन शामिल होंगे जिससे प्रत्येक भारतीय को लाभ मिलेगा।

युवा भारत के लिए आधारभूत संरचना

किसान भाईयों और युवाओं के लिए विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे एवं सड़कों का निर्माण कराया जाएगा ताकि स्कूल, बाजार और ऑफिस तक यातायात सुगम होगा।

सार्वजनिक यातायात सुविधा ज्यादातर लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक यातायात की दिशा में लखनऊ मेट्रो ने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।

लखनऊ मेट्रो सार्वजनिक परिवहन के लिहाज से शहर के भीतर सामाजिक एवं आर्थिक ताना-बाना बेहतर करने की की दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। मेट्रो लोगों के भीतर परस्पर करीबी बढ़ाने के साथ ही ट्रैफिक की समस्या से भी निजात दिला रही है। साथ ही सक्षम बाजारों को विकसित करने की दिशा में भी बेहतर काम कर रही है।

परिवर्तन के दौर दौर में भारत के युवा कौशल विकास करके अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं जोकि विशेष रूप से कठिन परिश्रम की अवधि है। शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे

शहर में जाना कभी भी आसान नहीं होता है। हम मानते हैं कि योग्य छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे कॉलेज मुहैया कराने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसके लिए हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके पास रहने के लिए सुरक्षित स्थान है।

अग्रणी कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों वाले शहरों में समाजवादी छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। आप पढ़ाई में प्रथम श्रेणी या डिस्टिंक्शन लाते हैं तो आपकों इन हॉस्टलों में ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

भारत के युवा व्यावसायिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। परन्तु हमारे पास स्टेडियम या ट्रेनिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ ऐसी सुविधाओं का विकास किया जाए ताकि उनके बच्चों को खेल का बेहतर वातावरण मिल सके। हम चाहते हैं कि स्थानीय लोग हमारे साथ आएं ताकि प्रत्येक गांव और कस्बे में खेल की सुविधाओं का विकास किया जा सके।

सरकार में आने पर हम लोग हर गांव में एक खेल का मैदान और प्रत्येक जिले में खेल सुविधाएं दिलाएंगे।

हम लोग पीपीपी मोड से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की हर तरह की सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करेंगे। सरकार बनने पर सभी तरह की ग्रामीण अवस्थापना को सशक्त करेंगे।

स्वर्णिम क्रांति

अन्नदाता किसान भाई हमारा पेट भरते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि वह भी भूखे न रहें। भाजपा की सरकार जबसे बनी है हमारे किसानों एवं ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कामगारों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। तेल और खाद की बढ़ती कीमतों ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है जिससे किसानों की आय और ग्रामीण मजदूरी में निरंतर कमी दर्ज की गई।

किसानों की समस्या राष्ट्रीय समस्या है और इसके समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होना चाहिए। कृषि संबंधित समस्या का निदान कोई भी प्रदेश सरकार अकेले नहीं कर सकती। हम लोग किसान भाईयों की प्रत्येक समस्या के साथ हर स्तर पर खड़े हैं और इस दिशा में जाति, पंथ या धर्म को भुलाकर स्वर्णिम क्रान्ति लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पूरे देश में किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हम देश के सभी किसानों के साथ बिना किसी जाति, धर्म और क्षेत्रीय भेदभाव के साथ खड़े हैं और हर स्थिति में स्वर्णिम क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस कड़ी में 100 फीसदी किसान कर्ज माफी हमारा पहला कदम होगा। क्योंकि 90 फीसदी किसान कर्ज के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। जो बैंकों की तरह कागजी कार्यवाही पर जोर नहीं देते हैं। हमें इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा।

इसके लिए हम समुदाय आधारित एवं प्रायोजित कर्ज सेवा मॉडल को बढ़ावा देंगे। जिसका नेतृत्व स्वयं सहायता प्राप्त समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। ये मॉडल केरल के सफलतम स्टेट फार्मर्स डेब्ट रिलीफ कमीशन पर आधारित है।

ऐसा मॉडल को केवल गठबंधन की सरकार ही जमीन पर उतार सकती हैं। क्योंकि ये केवल केंद्र सरकार के अकेले के बस की बात नहीं है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को संघीय ढांचे का लाभ उठाते हुए मिल कर काम करना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा, 'तथाकथित राष्ट्रवाद' नहीं

दिन पर दिन घबराई भाजपा भारतीय सेना को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिसका एक मात्र उद्देश्य सभी विपक्षी दलों को देशद्रोही करार देना है।

भाजपा का छद्म राष्ट्रवाद हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी बाहरी ताकत से ज्यादा खतरनाक है।

हमारी सुरक्षा बलों का बलिदान हमारी राष्ट्र की आत्मा और देश भक्ति के जज्बे पर आधारित है तथा किसी भी राजनीतिक सोच से कहीं ऊपर है।

हमारा मानना है कि राष्ट्र और नागरिकों के बीच नए सिरे से तालमेल करने की जरूरत है।

हम राजनीतिक फायदे के लिए सेना और सैनिकों के इस्तेमाल को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करेंगे। साथ ही उन सभी राज्यों में रेजिमेंट की स्थापना करेंगे जहां वर्तमान में रेजिमेंट नहीं है। हम अहीर बख्तरबंद रेजीमेंट और गुजरात इन्फेंट्री रेजीमेंट की स्थापना करेंगे।

उत्तर प्रदेश हमेशा से ही सैन्य बलों में भर्ती का मुख्य श्रोत रहा है।

हम देश सेवा में घर से बाहर रहने वाले सैन्य कर्मियों की पत्नियों एवं उनके परिवारों के लिए राज्य आधारित लोक कल्याण योजना की शुरुआत करेंगे।

समाजवादी पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को भारत के कुशल रक्षामंत्री के रूप में आज भी याद किया जाता है। उन्होंने बेहद कम समय में ही भारतीय वायु सेना को सुखोई विमान से लैस किया था।

हमारा विश्वास है कि सभी तरह के सुरक्षा बलों के जवानों को चाहे वे सेना के हों, बीएसएफ के हों या सीआरपीएफ के सभी का सम्मान और दर्जा बराबर होना चाहिए।

भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। हमारी विदेश नीति चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से मजबूती और दमदारी के साथ बात करने की होगी।

आंतरिक सुरक्षा – एक नया प्रतिमान

पिछले पांच सालों में भारत ने आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर अब तक के सबसे बदतर हालातों का सामना किया है। मौजूदा वक्त में हमने भारत को एकजुट रखने वाले सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न होते देखा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए इस बेहद खतरनाक हो चुकी स्थिति पर मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है।

चाहे महिला सुरक्षा का विषय हो या फिर गाय के नाम पर भीड़ द्वारा हत्या का मामला हो कानून व्यवस्था की स्थिति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है जिससे सामाजिक और स्वभाविक न्याय के सिद्धांत अमल में लाए जा सकें और ये महज जन आकांक्षाओं तक सीमित होकर ना रह जाएं।

हम भरोसा दिलाते हैं कि हम भारत राष्ट्र के लिए खतरा बन चुके नक्सलवाद से मुकाबला कर रहे केंद्रीय एवं राज्य सुरक्षा बलों को सशक्त बनाएंगे। आदिवासियों तक पहुंचने के लिए हम एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जिसका मूल उद्देश्य आदिवासियों के सम्मान, परम्परा, जल संपदा, जंगल और जमीन का सरंक्षण करना होगा।

चाहे लंबे अरसे से लंबित पुलिस रिफॉर्म्स हो या फिर खुफिया एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ावा देने का मामला हम लागू किए गए कानूनों का नवीनीकरण करेंगे जिससे हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नए देशविरोधी खतरों की पहचान और उनसे निपटने में सहायता मिले।

हम केंद्रीय एवं राज्य सुरक्षा बलों में भर्ती होने वाले नए सुरक्षाकर्मियों के लिए अत्याधुनिक हथियारों, संसाधनों और ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था और शुरुआत करेंगे।

NATGRID-राष्ट्र सुरक्षा की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए metadata intelligence grid- को पुन: शुरु किया जाएगा साथ ही इसको अत्याधुनिक तकनीक और मानव संसाधनों से लैस किया जाएगा।

हम भाजपा सरकार की कश्मीर नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे जिसने बड़े पैमाने पर कश्मीरी युवाओं में अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया है। हमारा मुख्य ध्यान संविधान के दायरे में व मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कश्मीर को देश के संघीय ढांचे के करीब लाने पर होगा।

स्वच्छ ऊर्जा अभियान और जातीय भेदभाव से मुक्ति

मौजूदा सरकार की फ्लैगशिप स्कीम स्वच्छ भारत योजना भारत को साफ सुथरा रखने में नाकाम रही है। इसमें दलितों एवं निचली जाति के लोगों से भेदभाव किया गया है।

प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धुल कर ऐसा संदेश देने की कोशिश की मानों ऐसा कर के उन्होंने सफाईकर्मियों को पवित्र कर दिया हो। इस घटना ने हमारे देश में जातीय भेदभाव की समस्या को और बढ़ावा दिया है।

अमीर और उच्च जाति के लोगों के लिए स्वच्छ भारत का निर्माण दलित और नीची जाति के लोगों को निशाना बना कर नहीं किया जा सकता। ये सामाजिक न्याय के उद्देश्यों के विपरीत है।

स्वच्छ भारत के तहत बने शौचालयों की सफाई का काम अभी भी स्वयं सफाई कर्मियों द्वारा अपने हाथों से ही किया जाता है। यह भारत के लिए कलंक है।

हमारा ऐसा मानना है कि 'स्वच्छ भारत' के विज्ञापन में खर्च होने वाले धन को सफाई के मूल संसाधनों, आधुनिक मशीनों की खरीदी के लिए किया जा सकता है। स्वच्छ हवा और शुद्ध पेयजल सबको उपलब्ध होना चाहिए।

ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले पर अत्यधिक निर्भरता जनजातीय जनसंख्या के जीवन को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉवर ग्रिड लगाने की क्षमता है जिसे अग्रणी ऊर्जा उत्पादक कम्पनियों के सहयोग से लगाया जाएगा।

महिलाओं को बराबरी का दर्जा

भाजपा अभी भी नारी शक्ति को पारम्परिक भूमिका में ही देखती है। भाजपा की मंशा महिलाओं को सिर्फ एक मां, एक बहन, एक पत्नी की भूमिका तक ही सीमित रखना है।

इस धारणा को बनाए रखने के लिए भाजपा की सोच महिलाओं को घर बैठा कर एक पत्नी, बहू और सास के रूप में रखने तक की ही है।

21वीं सदी में हम महिलाओं को बराबरी की नजरों से देखते हैं। उन्हे जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का भागीदार बनाएं। हमें उन्हें घर तक ही सीमित रखने की सोच को तोड़ना होगा।

हम सामाजिक शिक्षा आंदोलन पर काम करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षित करने का होगा- लड़कियों को बचाने की आवश्यकता नहीं बल्कि उन्हें बराबरी का दर्जा देते हुए सम्मान देने की जरूरत है। इस उद्देश्य को केवल कानून व्यवस्था दुरुस्त कर और महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म कर ही प्राप्त किया जा सकता है।

हम ऐसा मानते हैं कि सिर्फ संचार व्यवहार बदलने से काम नहीं चलेगा बल्कि वास्तविक बदलाव करने की आवश्यकता है। हम लोग समुचित प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, कानून-व्यवस्था को बढ़ावा देंगे एवं महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव को खत्म करेंगे।

आज महिलाओं की आवाज को सुनने और उनके अधिकारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभी को खुशहाल और समृद्ध बनाने का पुराना वादा आज भी अधूरा है। साथ ही सभी को प्रर्याप्त अवसर देने और सतत विकास के वादे भी झूठे निकले हैं।

आज हमारा मुख्य शत्रु अमीरी और गरीबी में बंटे वर्ग नहीं बल्कि पहचान में सीमित हो चुके वर्ग हैं।

आज हमारे दिल-दिमाग और संस्कारों में अहंकार भर चुका है। हमें समाज में अपने पहनावे के अनुसार चिह्नित किया जाता है। ना कि इस पर कि हम किस गरिमा से अपना जीवन-यापन कर रहे हैं।

आज हमें इस पर चिह्नित किया जा रहा है कि हम कितनी जोर से अपनी बात को रखते हैं। ना कि इस पर कि हमें क्या बोलना चाहिए और हम क्या जानते हैं।

आज हमें इस पर चिह्नित किया जा रहा है कि हम कितने दिखावे से प्रार्थना करते हैं ना कि इस पर कि हम अपनी दैनिक जीवन में किन मूल्यों का पालन कर रहे हैं।

आज के वक्त में हमें ऐसी सरकार की जरूरत है जो सभी के लिए काम करें ना कि चंद लोगों के लिए।

आज देश को ऐसी सरकार चाहिए जो वर्गों में बंट चुके समाज के बीच की खाई को पाट सके।

हमें ऐसी सरकार की जरूरत है जो संस्थाओं में घट रहे विश्वास को पुनर्जीवित कर सके कि हमारी जवाबदेही भारतीय संविधान के प्रति होनी चाहिए।

हम देश के उन 50 फीसदी लोगों को प्रोत्साहित करेंगे जो देश के महज 0.1 % लोगों से पीछे छूट गए हैं।

कृषि न सिर्फ हमारा अतीत है बल्कि हमारा भविष्य भी है। भारत दुनिया का पेट भरेगा और भारतीय किसान इससे होने वाले मुनाफे की फसल भी काटेंगे।

हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाते हुए इसे 21 वीं सदी के अनुरूप बनाएंगे। हम तब ऐसे छात्र दे सकेंगे जो विश्वपटल पर अपनी मेधा का प्रदर्शन कर सकेंगे।

हम छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हुए उन्हें बड़ा करेंगे जिससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। इसी तरह छोटी इकाइयों को मध्यम, मध्यम इकाइयों को बड़ी और बड़ी इकाइयों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने में मदद करेंगे।

हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां महिलाएं लंबे अरसे से चले आ रहे सभी भेदभावों को दरकिनार कर सम्मान जनक स्थान पा सकेंगी।

इन महत्वाकांक्षाओं को संघीय ढांचे में विश्वास रखते हुए राज्य और केंद्र सरकार के परस्पर सहयोग और एक साथ काम करने की भावना के साथ ही हकीकत में बदला जा सकता है।

VOTE FOR
#MAHAPARIVARTAN